

उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र आंदोलनों की भूमिका: राजस्थान के विशेष संदर्भ में

पुष्पेन्द्र पाराशर

शोधार्थी, जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

सारांश

उच्च शिक्षा संस्थान केवल ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक, राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक चेतना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छात्र आंदोलन इसी व्यापक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं, जिनके द्वारा विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याओं को सामूहिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान के उच्च शिक्षा संस्थानों के विशेष संदर्भ में छात्र आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य छात्र आंदोलनों के स्वरूप, कारणों, प्रमुख मुद्दों तथा उच्च शिक्षा व्यवस्था एवं छात्र समुदाय पर उनके प्रभाव को समझना है। राजस्थान में शुल्क वृद्धि, छात्रावास सुविधाएँ, परीक्षा एवं परिणाम संबंधी समस्याएँ, छात्र प्रतिनिधित्व, रोजगार, छात्रवृत्ति तथा संस्थागत प्रशासन से जुड़े मुद्दे छात्र आंदोलनों के प्रमुख आधार रहे हैं। अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक छात्र आंदोलन विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, राजनीतिक जागरूकता, सहभागिता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। साथ ही, उग्र आंदोलनों से उत्पन्न चुनौतियों का संतुलित मूल्यांकन आवश्यक है।

प्रमुख शब्द: छात्र आंदोलन, उच्च शिक्षा, राजस्थान, विद्यार्थी राजनीति, लोकतांत्रिक चेतना, छात्र प्रतिनिधित्व, नेतृत्व विकास, सामाजिक परिवर्तन।

परिचय

उच्च शिक्षा आधुनिक समाज में केवल ज्ञान एवं व्यावसायिक दक्षता प्रदान करने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों, आलोचनात्मक चिंतन तथा नागरिक उत्तरदायित्व के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं जहाँ विद्यार्थी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रश्नों पर विचार-विमर्श करते हैं। इसी संदर्भ में छात्र आंदोलनों को उच्च शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। छात्र आंदोलन सामान्यतः विद्यार्थियों द्वारा अपनी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक मांगों की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों को संदर्भित करते हैं। ये आंदोलन केवल तत्कालीन समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि विद्यार्थियों में सामूहिक चेतना, नेतृत्व क्षमता, सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास में भी योगदान करते हैं। विश्वविद्यालयों को लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के महत्वपूर्ण संस्थानों के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि यहाँ युवाओं को विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, असहमति तथा सार्वजनिक विमर्श में भागीदारी का अवसर प्राप्त होता है (यूनेस्को, 2021)।

भारत में छात्र आंदोलनों का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन तथा राष्ट्रवादी चेतना के विकास से भी जुड़ा हुआ है। औपनिवेशिक काल में विद्यार्थियों ने विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की। स्वतंत्रता के पश्चात् छात्र आंदोलनों का स्वरूप धीरे-धीरे शैक्षणिक सुविधाओं, छात्र अधिकारों, रोजगार, छात्रवृत्ति, शुल्क, सामाजिक न्याय और विश्वविद्यालय प्रशासन से संबंधित मुद्दों की ओर विस्तृत हुआ। विशेष रूप से 1960 और 1970 के दशकों में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति ने व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों को प्रभावित किया। इस प्रक्रिया ने छात्र समुदाय को केवल शिक्षा प्राप्त करने वाले समूह के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के सक्रिय अभिकर्ता के रूप में स्थापित किया। छात्र आंदोलनों के माध्यम से युवाओं ने शासन-व्यवस्था, सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे व्यापक मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस दृष्टि से छात्र आंदोलन युवा पीढ़ी की सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं (सिंह, 2018)।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र आंदोलनों का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वे विद्यार्थियों को निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं से जोड़ने तथा अपनी मांगों को संस्थागत स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हैं। लोकतंत्र केवल चुनावों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह संवाद, असहमति, सहभागिता और उत्तरदायित्व पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है। छात्र आंदोलनों के माध्यम से विद्यार्थी इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। वे संगठन निर्माण, नेतृत्व, संवाद, वार्ता, सामूहिक निर्णय तथा विरोध की लोकतांत्रिक पद्धतियों को सीखते हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालय परिसर लोकतांत्रिक नागरिकता के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी उच्च शिक्षा को आलोचनात्मक चिंतन, संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और समग्र व्यक्तित्व विकास से जोड़ने पर बल दिया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। इसलिए रचनात्मक एवं शांतिपूर्ण छात्र आंदोलनों को लोकतांत्रिक शिक्षा की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की भूमिका भी समय के साथ परिवर्तित हुई है। वर्तमान विद्यार्थी केवल पाठ्यक्रम एवं परीक्षा से संबंधित गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे संस्थागत प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण, लैंगिक समानता, रोजगार, डिजिटल अधिकार तथा सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर भी सक्रिय भागीदारी करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्र कल्याण, शिकायत निवारण तथा विद्यार्थियों की सहभागिता को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से जोड़कर देखा गया है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2023)। इस संदर्भ में छात्र प्रतिनिधित्व विद्यार्थियों और प्रशासन के बीच संवाद का माध्यम बन सकता है। यदि संस्थानों में शिकायतों के समाधान, संवाद और प्रतिनिधित्व की प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध हो, तो छात्र आंदोलनों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा प्रदान की जा सकती है। इसके विपरीत, जब विद्यार्थियों की समस्याओं को लंबे समय तक अनदेखा किया जाता है, तब असंतोष सामूहिक आंदोलन का रूप ग्रहण कर सकता है।

वर्तमान समय में छात्र आंदोलनों की प्रकृति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक माध्यमों और डिजिटल संचार के विस्तार ने विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं और मांगों को व्यापक स्तर पर व्यक्त करने का नया मंच प्रदान किया है। अब आंदोलन केवल परिसर-आधारित धरना, प्रदर्शन या ज्ञापन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डिजिटल अभियान, ऑनलाइन याचिका और सामाजिक माध्यमों के माध्यम से भी संचालित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप, आंदोलन के उग्र रूप, शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान तथा परिसर के वातावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव जैसी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। अतः छात्र आंदोलनों का मूल्यांकन केवल उनके विरोधात्मक स्वरूप के आधार पर नहीं, बल्कि उनके उद्देश्यों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रभावों और संस्थागत परिणामों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र आंदोलनों की भूमिका का राजस्थान के विशेष संदर्भ में अध्ययन प्रासंगिक हो जाता है। यह अध्ययन छात्र आंदोलनों के कारणों, स्वरूप, मुद्दों तथा उनके शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रभावों को समझने के साथ-साथ यह भी स्पष्ट करने का प्रयास

करता है कि छात्र राजनीति को किस प्रकार अधिक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और रचनात्मक बनाया जा सकता है। अध्ययन की प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आज उच्च शिक्षा संस्थानों से केवल कुशल मानव संसाधन तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि उनसे जागरूक, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक नागरिकों के निर्माण की भी अपेक्षा है। इस दृष्टि से छात्र आंदोलन उच्च शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और विद्यार्थियों की आकांक्षाओं के बीच संबंध स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम हैं। राजस्थान में इनके स्वरूप और प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन उच्च शिक्षा नीति, छात्र कल्याण तथा लोकतांत्रिक सहभागिता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोगी आधार प्रदान कर सकता है।

2. राजस्थान में छात्र आंदोलनों का स्वरूप एवं प्रमुख मुद्दे

राजस्थान में उच्च शिक्षा का विस्तार राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। राज्य में विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों तथा विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों के माध्यम से बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान की सामाजिक संरचना में ग्रामीण, अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विविध समुदायों की उपस्थिति है। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि भी समान नहीं है। अनेक विद्यार्थी ग्रामीण एवं निम्न आय वाले परिवारों से आते हैं, जिनके लिए उच्च शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक गतिशीलता और बेहतर रोजगार की संभावना का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसी परिस्थितियों में उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित समस्याएँ विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भविष्य के साथ-साथ उनके परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक आकांक्षाओं से भी जुड़ जाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने उच्च शिक्षा में समान अवसर, समावेशिता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विशेष बल दिया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में संस्थागत सुविधाओं और विद्यार्थी-केंद्रित प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में छात्र आंदोलनों का स्वरूप समय, परिस्थिति और मुद्दे के अनुसार अलग-अलग दिखाई देता है। सामान्यतः इनमें ज्ञापन देना, प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना, रैली, हस्ताक्षर अभियान, बहिष्कार, प्रतीकात्मक विरोध तथा सामाजिक माध्यमों के माध्यम से अभियान चलाना शामिल हैं। कुछ मामलों में विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन या सरकार के समक्ष अपनी मांगों को सामूहिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, जबकि गंभीर समस्याओं की स्थिति में आंदोलन अधिक व्यापक रूप ग्रहण कर लेते हैं। लोकतांत्रिक दृष्टि से शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संवाद आधारित आंदोलन विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं को संस्थागत स्तर पर व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विद्यार्थी कल्याण, शिकायत निवारण तथा सुरक्षित एवं समावेशी परिसर वातावरण को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण पक्ष माना है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2023)। इस दृष्टि से छात्र आंदोलन विद्यार्थियों और प्रशासन के बीच संवाद की एक वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में कार्य कर सकते हैं।

छात्र संघ एवं छात्र प्रतिनिधित्व राजस्थान में छात्र आंदोलनों की संरचना को समझने का महत्वपूर्ण आधार हैं। छात्र संघ विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने तथा उनके माध्यम से शैक्षणिक एवं प्रशासनिक समस्याओं को उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। छात्र प्रतिनिधि विद्यार्थियों और संस्थागत प्रशासन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। उनके माध्यम से विद्यार्थियों की सामूहिक मांगें अधिक संगठित रूप में सामने आती हैं। हालांकि छात्र प्रतिनिधित्व तभी प्रभावी हो सकता है जब उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी जाए। छात्र राजनीति का अत्यधिक राजनीतिकरण या बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप कभी-कभी छात्र हितों से जुड़े वास्तविक मुद्दों को पीछे कर सकता है। इसलिए छात्र संघों की भूमिका को विद्यार्थी कल्याण, शैक्षणिक सुधार और लोकतांत्रिक सहभागिता के संदर्भ में समझना आवश्यक है।

शुल्क, छात्रवृत्ति और आर्थिक समस्याएँ राजस्थान में छात्र आंदोलनों के प्रमुख आधारों में शामिल हैं। उच्च शिक्षा की लागत में वृद्धि का प्रभाव विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों पर पड़ता है। प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क, परिवहन तथा अध्ययन सामग्री का खर्च अनेक विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक दबाव उत्पन्न कर सकता है। छात्रवृत्ति की स्वीकृति में विलंब, छात्रवृत्ति की राशि समय

पर प्राप्त न होना तथा पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ न मिल पाना भी असंतोष का कारण बन सकता है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए विद्यार्थियों द्वारा आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्ति से संबंधित समस्याओं को उठाया जाना सामाजिक न्याय और समान शैक्षणिक अवसर की व्यापक अवधारणा से जुड़ा हुआ है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन, इंटरनेट तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता भी छात्र आंदोलनों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विशेष रूप से दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की पर्याप्त एवं सुरक्षित व्यवस्था उच्च शिक्षा की निरंतरता के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकें, डिजिटल संसाधन और अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। जब संस्थागत सुविधाएँ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होतीं, तो वे सामूहिक रूप से प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं से संबंधित आंदोलन केवल सुविधा प्राप्त करने का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अधिकार से भी जुड़े हुए हैं।

परीक्षा, परिणाम और प्रवेश से संबंधित समस्याएँ भी छात्र आंदोलनों के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। परीक्षा कार्यक्रम में अनावश्यक विलंब, परिणाम घोषित करने में देरी, परीक्षा परिणामों में त्रुटियाँ, पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में कठिनाई तथा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अस्पष्टता विद्यार्थियों में असंतोष उत्पन्न कर सकती है। उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र की नियमितता विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा और परिणाम में देरी का प्रभाव आगे की शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है। डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के बावजूद प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं समयबद्धता की आवश्यकता बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी संगठन प्रशासनिक सुधार तथा उत्तरदायित्व की मांग को आंदोलन का रूप दे सकते हैं।

रोजगार एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न भी राजस्थान के छात्र आंदोलनों को व्यापक सामाजिक संदर्भ प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की बड़ी आकांक्षा सरकारी एवं निजी क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करना होती है। परीक्षा आयोजित होने में देरी, परिणामों में विलंब, भर्ती प्रक्रिया की अनिश्चितता तथा रिक्त पदों की संख्या से संबंधित प्रश्न विद्यार्थियों और युवा समुदाय में असंतोष उत्पन्न कर सकते हैं। राजस्थान जैसे राज्य में प्रतियोगी परीक्षाएँ युवाओं के सामाजिक एवं आर्थिक भविष्य से सीधे जुड़ी हुई हैं। इसलिए रोजगार संबंधी छात्र आंदोलन केवल विश्वविद्यालय परिसर की समस्या नहीं रहते, बल्कि वे व्यापक युवा आकांक्षाओं एवं आर्थिक सुरक्षा के प्रश्न में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार छात्र राजनीति सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी बनती है।

राजस्थान में छात्र आंदोलनों पर सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों का प्रभाव भी उल्लेखनीय है। विभिन्न छात्र संगठन वैचारिक रूप से अलग-अलग राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधाराओं से प्रभावित रहे हैं। इन संगठनों के माध्यम से विद्यार्थियों को संगठनात्मक प्रशिक्षण, नेतृत्व का अनुभव और राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर, बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण छात्र आंदोलनों के मूल शैक्षणिक एवं विद्यार्थी-केंद्रित उद्देश्य प्रभावित होने की संभावना भी रहती है। अतः सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की भूमिका का मूल्यांकन संतुलित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। सकारात्मक स्थिति में ये संगठन विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यापक मंच प्रदान कर सकते हैं, जबकि अत्यधिक राजनीतिकरण आंदोलन को शैक्षणिक हितों से दूर कर सकता है।

3. छात्र आंदोलनों की भूमिका एवं प्रभाव

उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र आंदोलन विद्यार्थियों की सामूहिक चेतना, लोकतांत्रिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय केवल औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे सामाजिक परिसर हैं जहाँ विद्यार्थी विभिन्न विचारों, दृष्टिकोणों और सामाजिक अनुभवों के संपर्क में आते हैं। इस वातावरण में छात्र आंदोलन विद्यार्थियों को अपनी

समस्याओं, अधिकारों और अपेक्षाओं को सामूहिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। लोकतांत्रिक समाज में असहमति और विरोध को सामाजिक संवाद का स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। इसलिए शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से संचालित छात्र आंदोलन विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं तथा उनमें नागरिक चेतना विकसित करने में योगदान देते हैं (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

छात्र आंदोलनों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक चेतना का विकास है। आंदोलन के दौरान विद्यार्थी अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, सामूहिक निर्णय लेना, नेतृत्व का चयन करना, प्रशासन के साथ संवाद करना तथा अपनी बात को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना सीखते हैं। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से उनमें स्वतंत्र चिंतन, असहमति का सम्मान और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। विश्वविद्यालय परिसर में होने वाली बहस एवं विमर्श विद्यार्थियों को सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। इस प्रकार छात्र आंदोलन लोकतंत्र को केवल सैद्धांतिक विषय के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभव के रूप में समझने का अवसर देते हैं। उच्च शिक्षा में आलोचनात्मक चिंतन, संवैधानिक मूल्यों और जिम्मेदार नागरिकता के विकास पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जोर इसी व्यापक दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करता है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

छात्र आंदोलनों के माध्यम से नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक सहभागिता का भी विकास होता है। आंदोलन का संचालन विद्यार्थियों को संगठन निर्माण, संवाद, वक्तृत्व, रणनीति निर्धारण, संसाधन प्रबंधन और सामूहिक निर्णय जैसी क्षमताओं का अनुभव प्रदान करता है। छात्र प्रतिनिधि जब अपने साथियों की समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन या सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो उनमें सार्वजनिक नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में छात्र राजनीति ने अनेक युवाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश का अवसर दिया है। छात्र संघों एवं विद्यार्थी संगठनों में सक्रिय भागीदारी कई युवाओं के लिए राजनीतिक सामाजिककरण की प्रारंभिक अवस्था बनती है। हालांकि राजनीतिक सहभागिता तभी सकारात्मक परिणाम देती है जब वह लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता, वैचारिक सहिष्णुता और विद्यार्थी हितों पर आधारित हो। अत्यधिक राजनीतिकरण की स्थिति में छात्र हितों की अपेक्षा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रमुख हो सकती है, जो छात्र आंदोलनों की रचनात्मक भूमिका को सीमित कर सकती है।

छात्र आंदोलनों का योगदान सामाजिक परिवर्तन एवं जन-जागरूकता के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। विश्वविद्यालयों में सक्रिय विद्यार्थी जब सामाजिक असमानता, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार जैसे मुद्दों को उठाते हैं, तो उनका प्रभाव परिसर से बाहर समाज तक पहुँच सकता है। युवा वर्ग समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के प्रति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील होता है और नई विचारधाराओं तथा सामाजिक प्रश्नों को तेजी से स्वीकार करता है। इस कारण छात्र आंदोलनों को सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में भी देखा जाता है। राजस्थान में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रश्नों को व्यापक जनमंच पर उठाने की प्रवृत्ति ने युवा समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ाने में योगदान दिया है। डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने इस प्रभाव को और व्यापक बनाया है, क्योंकि अब किसी आंदोलन से संबंधित सूचना बहुत कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँच सकती है।

व्यक्तित्व विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से भी छात्र आंदोलनों का महत्व उल्लेखनीय है। सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने से विद्यार्थियों में संवाद, सहयोग, धैर्य, समस्या-समाधान और निर्णय लेने जैसी क्षमताओं का विकास हो सकता है। आंदोलन के दौरान विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि व्यक्तिगत समस्याएँ कई बार सामूहिक सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं। इससे उनमें दूसरों के अधिकारों और समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है। नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता विद्यार्थियों को भविष्य में अधिक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित कर सकती है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य भी केवल रोजगार प्राप्त करने योग्य मानव संसाधन तैयार करना नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से उत्तरदायी एवं नैतिक नागरिकों का निर्माण करना है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2020)।

हालाँकि छात्र आंदोलनों का शैक्षणिक वातावरण पर प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं होता। सकारात्मक स्थिति में आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान देने, सुविधाओं में सुधार करने तथा अधिक पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे संस्थागत लोकतंत्र और विद्यार्थी संतुष्टि बढ़ सकती है। इसके विपरीत, लंबे समय तक चलने वाले धरने, कक्षाओं का बहिष्कार, परीक्षाओं में व्यवधान, हिंसक प्रदर्शन या परिसर में तनाव की स्थिति शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उन विद्यार्थियों पर भी पड़ सकता है जो आंदोलन में शामिल नहीं हैं। इसलिए छात्र आंदोलनों के प्रभाव का मूल्यांकन उनके उद्देश्य और परिणाम दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः छात्र आंदोलनों को उच्च शिक्षा व्यवस्था में लोकतांत्रिक सहभागिता के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में समझना अधिक उचित है। ये आंदोलन विद्यार्थियों की आवाज को संस्थागत स्तर तक पहुँचाने, अधिकारों की रक्षा करने, नेतृत्व विकसित करने तथा सामाजिक चेतना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथ ही, इनके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए प्रशासनिक संवेदनशीलता, विद्यार्थियों की जिम्मेदार भागीदारी और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना आवश्यक है। राजस्थान के संदर्भ में छात्र आंदोलनों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि विश्वविद्यालय, सरकार और विद्यार्थी संगठन मिलकर असहमति को संघर्ष के बजाय संवाद और सुधार की प्रक्रिया में किस सीमा तक परिवर्तित कर पाते हैं।

4. चुनौतियाँ, बदलती प्रवृत्तियाँ एवं सुधार की संभावनाएँ

राजस्थान के उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र आंदोलनों की भूमिका को समझते समय उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा बदलते स्वरूप का अध्ययन आवश्यक है। छात्र आंदोलन लोकतांत्रिक सहभागिता, अधिकारों की अभिव्यक्ति और संस्थागत सुधार का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन इनके राजनीतिकरण, हिंसा, अनुशासनहीनता तथा शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान जैसी समस्याएँ इनके सकारात्मक प्रभाव को सीमित कर सकती हैं। वर्तमान समय में सामाजिक माध्यमों और डिजिटल संचार के विस्तार ने छात्र आंदोलनों की प्रकृति को भी बदल दिया है। इसलिए राजस्थान में छात्र आंदोलनों के भविष्य का मूल्यांकन केवल पारंपरिक छात्र राजनीति के आधार पर नहीं, बल्कि बदलती तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना आवश्यक है।

छात्र आंदोलनों के राजनीतिकरण की समस्या उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने प्रमुख चुनौती है। छात्र राजनीति लोकतांत्रिक नेतृत्व विकसित करने का माध्यम हो सकती है, किंतु जब विद्यार्थी संगठनों के मुद्दे व्यापक राजनीतिक दलों के हितों से अत्यधिक प्रभावित होने लगते हैं, तब वास्तविक शैक्षणिक एवं छात्र कल्याण संबंधी समस्याएँ पीछे छूट सकती हैं। छात्र संगठनों का वैचारिक जुड़ाव लोकतांत्रिक राजनीति का स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है, लेकिन बाहरी राजनीतिक हितों के कारण आंदोलन का उद्देश्य विद्यार्थी हित से हटकर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बन जाए, तो उसकी रचनात्मकता प्रभावित होती है। विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों की राजनीतिक अभिव्यक्ति के अधिकार और संस्थान की शैक्षणिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सुरक्षित, समावेशी और स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के निर्माण पर विशेष बल दिया है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2023)।

हिंसा, अनुशासनहीनता और शैक्षणिक व्यवधान छात्र आंदोलनों की दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती हैं। शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है, जबकि हिंसक गतिविधियाँ न केवल संस्थागत संपत्ति और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, बल्कि अन्य विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के शैक्षणिक अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। लंबे समय तक कक्षाओं का बहिष्कार, परीक्षा स्थगित करवाना, प्रशासनिक कार्यालयों में बाधा उत्पन्न करना या परिसर में तनाव की स्थिति बनना शिक्षा की निरंतरता को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी ऐसे व्यवधानों से अधिक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना और परीक्षा देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अतः आंदोलन की स्वतंत्रता और शैक्षणिक गतिविधियों की निरंतरता के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

वर्तमान समय में सामाजिक माध्यमों और डिजिटल माध्यमों ने छात्र आंदोलनों के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। पहले किसी आंदोलन के लिए परिसर में बैठक, पर्चे, पोस्टर, रैली और प्रत्यक्ष संपर्क प्रमुख साधन थे, जबकि अब विद्यार्थी संदेश, वीडियो, ऑनलाइन अभियान, डिजिटल पोस्टर, सामाजिक माध्यमों पर चर्चा तथा ऑनलाइन याचिकाओं के माध्यम से अपनी बात व्यापक स्तर तक पहुँचा सकते हैं। इससे आंदोलन अधिक तेजी से संगठित और प्रचारित किए जा सकते हैं। डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक पक्ष यह है कि वे विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का व्यापक मंच प्रदान करते हैं तथा प्रशासन तक शिकायतों को शीघ्र पहुँचाने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर, अपुष्ट सूचनाएँ, भ्रामक सामग्री, व्यक्तिगत आरोप तथा उत्तेजक संदेश आंदोलन को अनावश्यक रूप से उग्र बना सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता, तथ्य-जाँच और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना आवश्यक है।

विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच नियमित संवाद छात्र आंदोलनों से जुड़ी अनेक समस्याओं का समाधान कर सकता है। यदि विद्यार्थियों को अपनी समस्याएँ व्यक्त करने के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध हो और प्रशासन उनकी शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई करे, तो आंदोलन की आवश्यकता कई स्थितियों में कम हो सकती है। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में विद्यार्थी प्रतिनिधियों, शिक्षकों और प्रशासन के बीच नियमित संवाद समिति बनाई जा सकती है। ऐसी समितियाँ शुल्क, छात्रावास, परीक्षा, परिणाम, पुस्तकालय, छात्रवृत्ति तथा अन्य समस्याओं की समीक्षा कर सकती हैं। इससे प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता बढ़ेगी और विद्यार्थियों में संस्थान के प्रति विश्वास मजबूत होगा।

छात्र शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना भी आवश्यक है। शिकायतों की ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से प्राप्ति, शिकायतों की समयबद्ध समीक्षा, अपील की व्यवस्था तथा शिकायत के निस्तारण की पारदर्शी सूचना विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था आंदोलन के कारणों को प्रारंभिक स्तर पर पहचानने और उनका समाधान करने में सहायक हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विद्यार्थी शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित व्यवस्थाएँ इसी संस्थागत उत्तरदायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2023)।

छात्र नेतृत्व को रचनात्मक दिशा देने के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, वाद-विवाद, युवा संसद, सामुदायिक सेवा, सामाजिक जागरूकता अभियान, पर्यावरणीय गतिविधियाँ तथा विश्वविद्यालय विकास से संबंधित विद्यार्थी समितियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों की ऊर्जा को केवल विरोध और आंदोलन तक सीमित रखने के बजाय सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास से जोड़ा जा सकेगा। छात्र प्रतिनिधियों को संवैधानिक मूल्यों, संवाद कौशल, संघर्ष-समाधान और संस्थागत प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण देना भी उपयोगी होगा। समग्र रूप से देखा जाए तो छात्र आंदोलनों की चुनौतियों का समाधान आंदोलनों को प्रतिबंधित करने में नहीं, बल्कि उनकी लोकतांत्रिक और रचनात्मक क्षमता को मजबूत करने में निहित है। राजस्थान के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशासनिक संवेदनशीलता, विद्यार्थी सहभागिता, पारदर्शी शिकायत निवारण, जिम्मेदार छात्र नेतृत्व और डिजिटल माध्यमों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से छात्र आंदोलनों को संस्थागत सुधार की सकारात्मक शक्ति में बदला जा सकता है। इससे न केवल विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा होगी, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में लोकतांत्रिक संस्कृति, सामाजिक उत्तरदायित्व और शैक्षणिक गुणवत्ता को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा।

5. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के समग्र विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र आंदोलन केवल विरोध या असहमति की अभिव्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं लोकतांत्रिक चेतना से जुड़े महत्वपूर्ण माध्यम हैं। राजस्थान के विशेष संदर्भ में छात्र आंदोलनों का स्वरूप बहुआयामी दिखाई देता है। शुल्क, छात्रवृत्ति, छात्रावास, परीक्षा, परिणाम, प्रवेश, शैक्षणिक सुविधाएँ, रोजगार, छात्र प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे इनके प्रमुख आधार रहे हैं। इन आंदोलनों के माध्यम से विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को सामूहिक प्रश्न में

परिवर्तित करते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन तथा सरकार का ध्यान संबंधित समस्याओं की ओर आकर्षित करते हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि छात्र आंदोलनों की प्रभावशीलता उनके उद्देश्य, नेतृत्व, संगठनात्मक स्वरूप तथा अपनाए गए साधनों पर निर्भर करती है।

राजस्थान में छात्र आंदोलनों की समग्र भूमिका का मूल्यांकन करने पर इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष सामने आते हैं। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो छात्र आंदोलन विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, लोकतांत्रिक चेतना, संगठनात्मक कौशल और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करते हैं। ये आंदोलन विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने तथा संस्थागत व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दूसरी ओर, आंदोलनों का अत्यधिक राजनीतिकरण, बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप, हिंसा, अनुशासनहीनता और शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान इनके नकारात्मक पक्ष हैं। इसलिए छात्र आंदोलनों को न तो पूर्णतः समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए और न ही प्रत्येक आंदोलन को स्वतः लोकतांत्रिक एवं रचनात्मक मान लेना उचित होगा। इनके मूल्यांकन के लिए उद्देश्य, प्रक्रिया और परिणाम—तीनों को समान रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है।

लोकतांत्रिक मूल्यों एवं छात्र अधिकारों की दृष्टि से छात्र आंदोलनों का विशेष महत्व है। लोकतंत्र में विचार व्यक्त करने, असहमति दर्ज कराने और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार नागरिक सहभागिता का महत्वपूर्ण अंग है। विश्वविद्यालय परिसर विद्यार्थियों को इन अधिकारों के व्यावहारिक प्रयोग का अवसर प्रदान करता है। छात्र आंदोलन विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता करते हैं कि अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़े होते हैं। अतः छात्र आंदोलनों को संवैधानिक मूल्यों, अहिंसा, संवाद, सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी उच्च शिक्षा के माध्यम से आलोचनात्मक चिंतन, नैतिक मूल्यों, संवैधानिक चेतना और जिम्मेदार नागरिकता के विकास पर बल दिया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। इस दृष्टि से रचनात्मक छात्र राजनीति उच्च शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को मजबूत कर सकती है।

छात्र आंदोलनों के सकारात्मक पक्ष को मजबूत करने के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालयों में प्रभावी संवाद व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है। विद्यार्थियों और प्रशासन के बीच नियमित बैठकें, छात्र प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी तथा समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए। छात्र शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाने की आवश्यकता कम हो। इसके साथ ही छात्र प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व, संवाद, संघर्ष-समाधान, संवैधानिक मूल्यों और संस्थागत प्रक्रियाओं से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इससे छात्र राजनीति अधिक परिपक्व और उत्तरदायी बन सकती है।

छात्र संगठनों एवं छात्र नेताओं की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्हें विद्यार्थियों की वास्तविक समस्याओं को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर छात्र हित को स्थान देना चाहिए। आंदोलन के दौरान तथ्यपरक मांगों, शांतिपूर्ण साधनों और संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हिंसा, व्यक्तिगत आरोप, संपत्ति की क्षति तथा शैक्षणिक गतिविधियों में अनावश्यक व्यवधान से बचना आवश्यक है। सामाजिक माध्यमों का उपयोग भी जिम्मेदारीपूर्वक किया जाना चाहिए। अपुष्ट सूचनाओं और भ्रामक सामग्री के प्रसार से बचते हुए डिजिटल माध्यमों को जन-जागरूकता और संवाद के प्रभावी साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

भविष्य में शांतिपूर्ण, रचनात्मक एवं उत्तरदायी छात्र राजनीति की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने विद्यार्थियों को नए प्रकार की सहभागिता के अवसर दिए हैं। छात्र संगठन यदि रोजगार, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, लैंगिक समानता, शैक्षणिक गुणवत्ता और सामुदायिक विकास जैसे विषयों को अपने एजेंडे में शामिल करें, तो उनकी सामाजिक उपयोगिता और बढ़ सकती है। छात्र राजनीति को केवल चुनाव और विरोध की गतिविधियों तक सीमित न रखकर नेतृत्व विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

- शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2020)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*। भारत सरकार।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। (2023)। *उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण हेतु विनियम*। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। (2020)। *उच्च शिक्षा में गुणवत्ता अधिदेश एवं विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा संबंधी दिशा-निर्देश*। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। (2020)। *उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थी कल्याण एवं समावेशी शिक्षा संबंधी दिशा-निर्देश*। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- शिक्षा मंत्रालय। (2021)। *भारत में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण: 2019-20*। भारत सरकार, नई दिल्ली।
- शिक्षा मंत्रालय। (2023)। *भारत में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण: 2021-22*। भारत सरकार, नई दिल्ली।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। (2019)। *उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र शिकायत निवारण एवं विद्यार्थी कल्याण संबंधी दिशा-निर्देश*। नई दिल्ली।
- राजस्थान सरकार। (2023)। *उच्च शिक्षा विभाग: वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23*। उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- राजस्थान सरकार। (2024)। *राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24*। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- राजस्थान विश्वविद्यालय। (2023)। *वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23*। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। (2023)। *वार्षिक प्रतिवेदन*। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
- शर्मा, आर. के. (2018)। *भारतीय समाज एवं सामाजिक परिवर्तन*। रावत प्रकाशन।
- सिंह, वी. पी. (2018)। *भारतीय राजनीति में युवा एवं छात्र सहभागिता*। नई दिल्ली: ज्ञान प्रकाशन।
- वर्मा, एस. (2019)। *भारतीय लोकतंत्र और युवा राजनीति*। जयपुर: राज पब्लिशिंग हाउस।
- चौधरी, आर. एस. (2020)। *राजस्थान में उच्च शिक्षा: विकास एवं चुनौतियाँ*। जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
- गुप्ता, पी. (2021)। *शिक्षा, युवा और सामाजिक परिवर्तन*। नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
- कुमार, ए. (2019)। *उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय*। नई दिल्ली: शैक्षिक प्रकाशन।
- प्रसाद, एम. (2020)। *भारतीय लोकतंत्र में युवा शक्ति की भूमिका*। नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
- मिश्रा, एस. (2021)। *छात्र राजनीति और भारतीय लोकतंत्र*। नई दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन।
- नायक, आर. (2022)। *राजस्थान में युवा राजनीति एवं सामाजिक परिवर्तन*। जयपुर: साहित्यागार।
- विश्व बैंक। (2019)। *विश्व विकास रिपोर्ट 2019: बदलते कार्य की प्रकृति*। विश्व बैंक, वाशिंगटन, डी.सी.
- यूनेस्को। (2021)। *उच्च शिक्षा एवं सतत विकास: वैश्विक परिप्रेक्ष्य*। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन।
- संयुक्त राष्ट्र। (2020)। *विश्व युवा रिपोर्ट: युवा सामाजिक नवाचार एवं परिवर्तन*। संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क।
- भारत सरकार। (2023)। *भारत में युवा: युवा विकास एवं सहभागिता संबंधी रिपोर्ट*। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। (2022)। *भारत में उच्च शिक्षा: प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ*। नई दिल्ली।

Cite the Article:

पाराशर, पुष्पेन्द्र . (2026). उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र आंदोलनों की भूमिका: राजस्थान के विशेष संदर्भ में. Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, 3(4) 689-706, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 04, June-2026. DOI:- <https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.75>



This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.



CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

पुष्पेन्द्र पाराशर

For publication of research paper title

उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र आंदोलनों की भूमिका: राजस्थान के विशेष
संदर्भ में

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed
Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03,
Issue-04, Month June 2026, Impact Factor-RPRI-3.89/6.69

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and
the paper must be available online at: <https://shikshasamvad.com/>

DOI:- <https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.75>